

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771

86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc.

ARTCLE WORLD, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952

चोर को पकड़ने में बशिष्ठ पुलिस ने दिखाई तत्परता

गुवाहाटी (हिस)। बशिष्ठ पुलिस ने चोरी की एक शिकायत मिलने के महज 24 घंटे के भीतर कुख्यात चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान दीपज्योति कलिता उर्फ बाबू (19) के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। यह अभियान महीबुल इस्लाम (55) के किराना दुकान में चलाया गया। तलाशी के दौरान दुकान से कुछ चोरी के सामान बरामद किए गए और महीबुल इस्लाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

पाकिस्तान समर्थकों को ...

नहीं की जा सकती। कांग्रेस के दौर में *सूता और कम्बल* वाली राजनीति होती थी, आज विकास की राजनीति हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह *लुगी* होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कोकराझाड़, ग्वालपाड़ा सहित कई जिलों में मुस्लिमों का कल्लेआम हुआ था, जबकि आज असम में शांति है। आगे वादों का जिक्र करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी से बारपानी, बारपानी से पाथरग्राम तक सड़क परियोजना शुरू की है, जिससे यात्रा केवल चार घंटे में पूरी होगी। रामकृष्णनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य कारण गंगा और हैलाकांदी में एक नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। बराक घाटी के तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 22 हजार अरुणोदय लाभाधारियों की संख्या बढ़ाकर 40 हजार की जाएगी, ताकि कोई गरीब वंचित न रहे। डॉ. शर्मा ने कहा कि जून महीने में वे फिर श्रीभूमि आएंगे और स्वयंसेवी समूह की महिलाओं को 10–10 हजार रुपए के चेक अपने हाथों से वितरित करेंगे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में राशन कार्ड का कोई मूल्य नहीं था, जबकि अब राशन कार्ड से न केवल मुफ्त राशन, बल्कि पांच लाख रुपए तक का बीमा भी मिलता है। कॉलेज में दाखिले के लिए अब पंचायत सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, राशन कार्ड ही काफी होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 01 अक्टूबर से चावल, दाल, नमक आदि बाजार मूल्य से 30 रुपए सस्ता मिलेगा। रसोई गैस सिलेंडर 987 रुपए में मिलेगा, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर की कीमत 550 रुपए होगी। इसके अलावा सामान्य गैस सिलेंडर 600 रुपए और उज्ज्वला सिलेंडर 250 रुपए में मिलेगा। साथ ही ट्यूटर, ऑनलाइन और आशा कार्यक्रमोंओं तथा मिड-डे मील कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी।

पंचायत चुनाव : भाजपा का ...

या संकल्प पत्र में 15 प्रमुख प्रतिज्ञाओं की रूपरेखा दी गई है, जिसमें किसानों और ग्रामीण आजीविका पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक प्रमुख वादा मुआवजे के नियमों में महत्वपूर्ण सुधार का है – अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वह प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की निशेष 33 प्रतिशत फसल बर्बाद होने पर भी उन्हें वित्तीय राहत देगी। मुआवजे के लिए मौजूदा सीमा 60 प्रतिशत है। छोटे पैमाने के किसानों और डेयरी किसानों की और अधिक सहायता देने के लिए, पार्टी ने हाट बाजारों के लिए कर माफ करने तथा उपस्थान और सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए उन्तत बीज, उर्वरक और सौर ऊर्जा चालित पंप शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। घोषणापत्र में गांवों में छोटे बांध बनाने और शैशोनीकरण में सहायता के लिए पर्यटक गांव को ट्रेक्टर उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल है। तकनीक, कल्याण और बुनियादी ढांचा डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए भाजपा ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट का वादा किया है – इस कदम से दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफार्मों तक पहुंच को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। घोषणापत्र में प्रत्येक गांव में एक आधुनिक, अच्छी तरह से सुसज्जित श्मशान घाट बनाने का भी वादा किया गया है, तथा मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं जैसे संतुष्ट मैना, मिशन वसुंधरा, महिला उद्यमिता योजना, बीपीएल परिवारों के लिए राशन कार्ड और युवाओं के लिए उद्यमिता समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। जैसे-जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, भाजपा को उम्मीद है कि निरंतरता के साथ-साथ आक्रामक पहुंच और लक्षित ग्रामीण कल्याण के प्रयासों से राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में उसका प्रभुत्व और मजबूत होगा – जिसकी शुरुआत जमीनी स्तर से होगी।

बराक घाटी के बिना...

बीच संघर्ष अतीत की बात हो गई है। आज, यह एक अलग असम है – एक प्रगतिशील असम। क्षेत्र के लिए आगामी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सुचीबद्ध करते हुए, शर्मा ने 25,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बारपानी-पंचग्राम हाई-स्पीड सड़क, सिलचर-सौराष्ट्र महासड़क और मधुपराघर पर 90 करोड़ रुपए के पुल सहित अन्य परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक बार सड़क नेटवर्क परियोजना पूरी हो जाने पर दक्षिणी असम के निवासी आसानी से राज्य की राजधानी तक पहुंच सकेगे, ठीक उसी तरह जैसे असम के बाकी हिस्से के लोग बराक घाटी तक आराम से यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आगामी पंचायत चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगी असम गण परिषद द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के लिए भी लोगों में समर्थन उम्मीद।

पीओके में आतंकियों के 42 लॉन्च पैड एक्टिव

ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना ने बनाया प्लान

नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। भारतीय सेना पूरी तरह एक्शन मोड में है और जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। बोते छह महीनों में सीमा पर घुसपैठ की करीब 45 कोशिशों को नाकाम किया गया है। पिछले साल भी सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की 10 कोशिशों को नाकाम कर 25 आतंकवादियों को ढेर किया था। एलओसी के पार, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में इस वकत करीब 42 लॉन्च पैड सक्रिय हैं, जिनमें अनुमानतः 110 से 130 आतंकवादी छिपे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इन लॉन्च पैडों में कश्मीर में 35–40 लॉन्च पैड हैं। वहीं बाकी राजौरी, जम्मू और पुंछ जैसे इलाकों में मौजूद हैं। जम्मू-कश्मीर में इस समय 125 से 130 आतंकवादी एक्टिव बताए जा रहे हैं। इनमें से 70–75 आतंकी कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं, तो 60-65 आतंकवादी जम्मू, राजौरी और पुंछ के

इलाकों में एक्टिव बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2022 में 107 आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इनमें 186 आतंकवादी को मार गिराया गया। वहीं, साल 2023 में 27 आतंकवादी घटनाएं घटी हैं इनमें 76 आतंकी को ढेर किया गया। साल 2024 में अब तक 26 घटनाएं दर्ज हुई हैं। मार्च तक सिर्फ 3 हमले हुए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों और सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त करने की प्लानिंग बना रही है। हाल में पहलगाम में आतंकी हमले में कुल 26 निहत्थे नागरिकों को भून डाला गया था। खुफिया एजेंसी का कहना है कि इस हमले में पाकिस्तान की मदद के सबूत मिले हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना की ओर से इन घुसपैठों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इस असफल घुसपैठ के प्रयास के दौरान 642 मुजाहिद बटालियन को

भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा, हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कुल 60 विदेशी आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में सक्रिय हैं। इस साल, पाकिस्तानी सेना की ओर से बार–बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, केवल जम्मू-कश्मीर में इस साल तीन बार संघर्ष विराम का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। इस दौरान भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में पांच आतंकवादी मारे गए। जम्मू और कश्मीर के नौ जिलों में जहां विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, बारामुस्ला आतंकवादी हताहतों की सूची में सबसे ऊपर है, जहां नौ मुठभेड़ों में 14 गैर-स्थानीय आतंकवादी मारे गए हैं। उनमें से ज्यादातर उरी सेक्टर के सबुरा नाला इलाके, मेन उरी सेक्टर, एलओसी के पास कमालकोट उरी और सोपोर के चक टम्पर क्रिरी, नौपोरा, हादीपोरा, सागीपोरा, वाटरगाम और राजपोर इलाकों के अरंदूनी इलाकों में मारे गए।

पूसीरे सीसीटीवी निगरानी के साथ

समपार फाटकों पर यात्री सुरक्षा बढ़ाई

गुवाहाटी (हिस)।मानवीय भूल को कम करने, क्रांसिंग पर होने वाली घटनाओं को न्यूनतम करने तथा सुरक्षित, निर्बाध रेल यातायात सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) की व्यापक रणनीति तैयार है। प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कवरेज सतर्कता को बढ़ाता है, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को गति देता है तथा डेटा आधारित सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करता है। इसके अतिरिक्त, कटिहार, अलीपुरद्वार, लामडिंग तथा तिनसुकिया मंडलों में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोस्ट पर 09 इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा, अलीपुरद्वार मंडल के हासीमारा-कालचीनी सेक्शन में आईबीएस

(इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग) हट्स पर 06 कैमरे लगाए गए हैं, ताकि दूरस्थ सिग्नलिंग स्थानों पर निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके। पूसीरे के सीपीआरओ कर्पिंजन किशोर शर्मा ने आज बताया है कि अपने बुनियादी संरचनाओं के आधुनिकीकरण कार्यों के हिस्से के रूप में पूसीरे ने अपने सभी मंडलों में महत्वपूर्ण एलसी फाटकों पर इंटरलॉकिंग सिस्टम लागू किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फाटक पूरी तरह से ट्रेन के आवागमन के साथ समन्वयित हैं। यह प्रणाली बैरियर को आने वाली ट्रेनों के साथ प्रत्यक्ष समन्वय में संचालित करने की अनुमति देती है, जिससे सूचारु और सुरक्षित क्रांसिंग की गारंटी मिलती है।

पृष्ठ एक का शेष

नेहरु की सिंधु जल...

प्रतिवर्ष 135 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी प्राप्त हुआ, जबकि भारत के पास केवल 33 एमएएफ पानी बचा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे भी बुरी बात यह है कि पश्चिमी नदियों पर भारत के अधिकार केवल छोटी सिंचाई और बिना किसी सार्थक भंडारण के रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रो परियोजनाओं तक सीमित थे, जिससे पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की पानी की जरूरतें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के लिए नेहरु का गलत गुप्त रूप भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की कीमत पर आया, जिससे भारत की अपनी जमीन पर रणनीतिक और कृषि शक्ति कमजोर हो गई। सिंधु जल संधि को निर्लांबित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना करते हुए सीएम शर्मा ने लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अन्याय पर ऐतिहासिक प्रहार किया है। संधि से भारत के हटने की पहल करके मोदी ने अपनी नदियों पर भारत के संप्रभु अधिकारों को पुनः प्राप्त किया है, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि भारत अब आतंक और शत्रुता को तुष्टिकरण से पुरस्कृत नहीं करेगा। इस निर्णय को एक *साहसिक कदम* बताते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह पाकिस्तान को नाजुक अर्थव्यवस्था पर प्रहार है, जहां 75 प्रतिशत से अधिक कृषि सिंधु जल पर निर्भर है।

दिल्ली के महत्वपूर्ण ...

लहर दौड़ गई है। उल्लेखनीय है कि उपेंद्रनाथ ब्रसम को *बोडोफा* की उपाधि दी गई थी और उन्होंने बोडो समुदाय और बोडोलैंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली में सड़क का यह नामकरण उत्तर-पूर्व भारत के लोगों के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है।

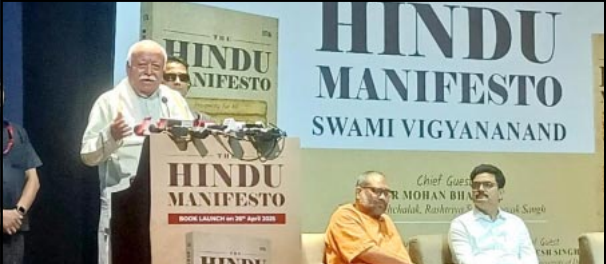
सेना की गतिविधियों ...

है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा और अन्य सुरक्षा-संबंधी अभियानों से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी का बर्तें और मौजूदा कानूनों और विनियमों का सख्ती से पालन करें। सलाह में कहा गया कि रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से जुड़ी कोई भी कवरेज, दृश्य प्रसारण या स्रोतों से प्राप्त जानकारी आधारित रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा दुश्मनों की मदद कर सकता है और इससे ऑपरेशनल प्रभावशीलता और सुरक्षा कर्मियों की जान को खतरा हो सकता है। इस दौरान मंत्रालय के सलाह में 1999 के कारगिल युद्ध, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले और कंधार हाइड्रोजेन जैसे घटनाओं का जिक्र किया गया, जब अविचारपूर्ण कवरेज के कारण राष्ट्रीय हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

गुजरात में अवैध अप्रवासियों ...

अप्रवासियों ने गुजरात आने से पहले भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने के लिए पश्चिम बंगाल से प्राप्त फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इनमें से कई लोग मादक पदार्थ तस्करी और मानव तस्करी में संलिप्त हैं। हाल ही में गिरफ्तार किए गए चार बांग्लादेशियों में से दो अलकायदा के स्लीपर सेल में काम करते थे। इन बांग्लादेशियों को पृष्ठभूमि और गुजरात में उनकी गतिविधियों की जांच की जाएगी। इनके निर्वासन की सभी प्रक्रियाएं यथाशीघ्र पूरी करने के लिए व्यवस्था की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि हम उन फर्जी दस्तावेजों की भी जांच करेंगे जिनका इस्तेमाल उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों और गुजरात तक पहुंचने के लिए किया और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को गुजरात भर में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों को गुजरात छोड़ने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल को इस बात का सबूत दिया जाएगा कि बंदि्यों ने राज्य में कैसे फर्जी दस्तावेज बनाए? गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वास सहाय ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा दस्तावेजी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उनकी पृष्ठभूमि का पता लगाया जा रहा है। जब यह यह हो जाएगा कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं, तो केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के समन्वय से उनके निर्वासन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानियों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। इसी नीति के आधार पर पाकिस्तान के लोगों को देश छोड़ने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि

हिन्दू समाज अपने धर्म के मूल्यों को समझे : मोहन भागवत



नई दिल्ली (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का कहना है कि हिन्दू समाज ही पहले हिन्दू धर्म को ठीक से समझेघ हिन्दू मेनिफेस्टो नामक एक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए उन्होंने एक बार फिर दोहराया की राजा का धर्म है कि वह अपने समाज और उसके नागरिकों की रक्षा करेंघ उन्होंने कहा कि विश्व में अनेक प्रकार की सभ्यताएं दोगाहे पर खड़ी हैं और भविष्य का मार्ग ढूंढ रही हैं। यह मार्ग भारत ही उन्हें दिखा सकता है लेकिन उससे पहले भारत को स्वयं पूर्ण दृष्टि वाला समर्थ और सबल भारत बनकर खड़ा होना होगा आईआईटी खड़गपुर के स्नातक और संन्यासी स्वामी विज्ञानानंद की शोध पूर्ण और काल संगत पुस्तक द हिंदू मेनिफेस्टो की प्रशंसा करते हुए डॉ. भागवत ने कहा कि यह पुस्तक एक विमर्श पैदा करेगी, भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगी घ हिन्दू धर्म की बौद्धिक संपदा और उसकी वैश्विक दृष्टि को लोगों के बीच तक पहुंचाने का काम करेगी। लोकार्पण समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री संग्रहालय और

पुस्तकालय परिसर में किया गया। डॉ. भागवत ने कहा कि सनातन हिन्दू समाज की दृष्टि को लोगों तक पहुंचाना यह समय की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात ठीक है कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और हमारी अहिंसा लोगों की सोच को बदलने के लिए है, पर जब कोई सोच नहीं बदलता है तो उसको दंडित करना भी धर्म ही होता है घ हमने राम रावण युद्ध में इसे देखा है। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ योगेश कुमार ने हिन्दू चिंतन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ चिंतन बताते हुए कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव इसी दृष्टिकोण में से निकला है। स्वामी विज्ञानानंद ने हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत के धारा प्रभाव भाषण में पुस्तक में जो सामग्री संकलित की गई है इसका सक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वेदों उपनिषदों आदि के माध्यम से यह स्पष्ट सिद्ध किया है की समृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिम्मेदार लोकतंत्र, महिलाओं के प्रति सम्मान, सामाजिक सद्भाव, प्रकृति की पवित्रता और मातृभूमि के प्रति सम्मान इन आठ मार्गदर्शन सिद्धांतों पर चलकर भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता हैघ उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ शोध किया है और उसके संदर्भ भी दिए हैं इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाल्मीकि मंदिर के प्रमुख स्वामी कृष्ण शाही विद्यार्थी जी महाराज ने आशीर्वाचन दिया।

ईरान में भीषण धमाका, चार की मौत, 500 से ज्यादा घायल

तेहरान। ईरान के बंदर अब्बास शहर में शनिवार को भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई। ये जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी ने दी है। जानकारी के मुताबिक, अभी तक इस धमाके में चार लोगों की मौत और 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह विस्फोट बंदर अब्बास शहर के रजई बंदरगाह पर हुआ है। वहीं इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं, जिसमें धमाके के बाद काले धुएँ का विशाल गुबार देखा जा सकता है।



जबकि इस मामले में अधिकारियों ने विस्फोट का तत्काल कोई कारण नहीं बताया। बता दें कि, रजई बंदरगाह ईरान के बंदरगाहों में से एक

के शीशे टूट गए और घरो-ऑफिसों को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका दोपहर के 12 बजे हुआ है।

पाकिस्तान के लोगों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित समय से अधिक समय भारत में रुकता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पहलगाम : युवती ने ...

बात की। प्राथमिक जांच में पता चला है कि दो फर्जी फेसबुक अकाउंट से धमकी दी गई है। धमकी देने वालों ने युवती के पोस्ट को धार्मिक विद्वेष फैलाने वाला बताया है। वहीं, पीड़िता ने कहा कि पहलगाम में जिस तरह से हिंदू पर्यटकों को चुन-चुनकर उनकी हत्या की गई, वह बेहद निंदनीय है। उसी का विरोध करते हुए उन्होंने पोस्ट किया था। अधिकशां लोगों ने उनके पोस्ट का समर्थन किया है। दूसरी तरफ कोलकाता की संस्था भवानीपुर गुजराती एजुकेशन सोसाइटी ने आतंकी हमले में मारे गए बंगाल के तीन लोगों की संतानों की शिक्षा के लिए 10–10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मालूम हो कि मरने वालों में से दो कोलकाता व एक पुरुलिया जिले के झालदा के रहने वाले थे।

नूंह में भीषण सड़क ...

घायल एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। अभी भी दो महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वाली महिलाओं में चार महिलाएं एक ही परिवार की है। हादसा होने के बाद पिकअप गाड़ी का चालक फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान खेड़ली कलां गांव की रहने वाली 30 वर्षीय रचना, 30 वर्षीय पिस्ता, 60 वर्षीय रेशम, 30 वर्षीय सतवंत, 50 वर्षीय जयदेई, 65 वर्षीय प्रेम और झिमरावट निवासी 50 वर्षीय आशु के रूप में हुई है। इसके अलावा गांव रिगड़ निवासी अनिता, लच्छन और हेमलता गंभीर रूप से घायल हुई हैं। चौथी घायल महिला की अभी पहचान नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद की जाएगी और घायलों का उचित इलाज कराया जाएगा। एमपी राजेश कुमार ने कहा कि आरोपित ड्राइवर की जल्द ही पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और शवों को अल आफिया अस्पताल मांडीखंडा में रखवा दिया है।

सरेआम भारतीयों का...

पाकिस्तानी सेना के रक्षा आगोशे कर्नल तैमूर रावत, जो लंदन स्थित पाकिस्तानी मिशन में तैनात हैं, ने दूतावास की बालकनी से भारतीय प्रदर्शनकारियों की ओर सिर काटने का इशारा किया हो नहीं किया बल्कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर भी दिखाई, जिस पर *चाय इन फेंट्स* लिखा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भारतीय छात्रों ने रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें पाक अधिकारी का व्यवहार साफ नजर आता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से एक, तेजस भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कर्नल रावत ने जानबूझकर उतेजक हरकत की, लेकिन भारतीय प्रदर्शनकारी शांत रहे और विरोध जारी रखा। पाक अधिकारी द्वारा अभिनंदन की तस्वीर दिखाना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान अब भी 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक को घटना को लेकर बौखलाया हुआ है। गौरतलब है कि विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी विमान को मार गिराया था, और पाक की गिरफ्त में आने के बाद भारत के दबाव में उन्हें रिहा करना पड़ा था। उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया था। ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देश में एक विदेशी मिशन के अधिकारी द्वारा इस प्रकार की धमकी और इशारा करना न केवल कूटनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि यह साफ दर्शाता है कि आतंक का समर्थन पाकिस्तान की सरकारी सोच में गहराई तक समाया हुआ है। भारत सरकार से उम्मीद जताई जा रही है कि वह इस घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाएगी और ब्रिटेन सरकार से औपचारिक शिकायत कर इस मामले में कार्रवाई की मांग करेगी। बता दें बीते मंगलवार को पहलगाम के बैसारन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में 26 निंदीय लोग मारे गए थे, जिनमें कई पर्यटक शामिल थे। इस हमले के खिलाफ दुनिया भर में बसे भारतीय विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लंदन में हुआ यह प्रदर्शन भी उसी कड़ी का हिस्सा था।

रोजगार मेला : पीएम मोदी ...

कि जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं, तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इन्वोेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हममें कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के

युवाओं के लिए रोजगार-स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में सरकार ने मैनुफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है- मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रॉडक्ट बनाने का मौका देना। इससे ना केवल देश की लाखों एमएसएमईएस को...हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि आज का ये समय भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। हाल ही में आईएमएफ ने कहा है कि भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। देश में युवाओं के लिए नए नए अवसर बन रहे हैं। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड आीडियो वीजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानि, वेध्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इस तरह का मंच मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज जो कॉर्निमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है और हमारी बेटियां दो कदम आगे ही चल रही हैं। हमारी नारीशक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलाईयों को छू रही है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए- नागरिक देवो भवः। मुझे विश्वास है कि अपने साामर्थ्य और ईमानदारी से एक ऐसा भारत बनाएंगे, जो विकसित भी होगा और समृद्ध भी होगा।

हिंदू-मुस्लिम एक ...

अपने बच्चों को देश की कहानी सुनाने को कहा था। मुनीर ने कहा कि मुसलमान जीवन के सभी पहलुओं धर्म, रीति-रिवाज, परंपरा, सोच और आकांक्षाओं में हिंदुओं से अलग हैं। दरअसल मुनिर अपने आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान की आवाम में अपनी ही सरकार के खिलाफ उठ रही विद्रोह की आवाज को भटकाने के लिए ऐसे उलट-जलूल बयान देते रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ तनाव के बीच उठने इस बयान को भी इसी रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सख्त रुख से वहां की आवाम भी खोफजदा है। इससे ध्यान भटकाने के लिए मुनीर ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए बहुत बलिदान दिया। हम जानते हैं कि इसका बचाव कैसे करना है। जिना की टू नेशन थियरी का जिक्र करते हुए मुनीर ने कहा कि मारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति-रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यहीं पर दो-राष्ट्र सिद्धांत में रंभे रखी गई थी। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं हैं।

हर पाकिस्तानी को ...

तरह लागू होगा। हर पाकिस्तानी नागरिक को वापस जाना पड़ेगा। उपमचुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ देने को कहा गया है और यह समय सीमा कल 27 अप्रैल को समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, उनकी पहचान कर ली गई है और जरूरत पड़ी तो उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वीजा रद्द होने के बाद किसी पाकिस्तानी के यहां रहने का कोई सवाल ही नहीं है। जो नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चौधरी ने कहा कि पहलगाम की आतंकी हिंसा भारत पर हमला है। दुःख और आक्रोश के इस समय में पूरा देश एकजुट है। इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के आकाओं को मिट्टी में मिला देने का कड़ा संकल्प ले लिया है, तो उसे पूरा करने में बिहार हर कदम पर साथ खड़ा रहेगा। चौधरी ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने पहलगाम नरसंहार में अपनी नापक सत्तिपत्ता स्वीकार करने के बजाय भारत से टकराव का रुख अपनाया और पिछले युद्ध के बाद हुआ शिमला समझौता रद्द कर दिया है, तो यह अच्छा ही है। अब भारत उनकी सीमा में घुसकर बदला लेगा।

उत्तराखंड में अब ...

को सील किया जा चुका है। आज की कार्रवाई के साथ प्रदेश में अब तक कुल 180 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के दायरे से बाहर कोई भी संस्था संचालित नहीं होने दी जाएगी और इस प्रकार की कार्रवाइयां आगे भी निरंतर जारी रहेंगी। एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने हल्लू माजार, मक्खनपुर और मोहितपुर गांवों में स्थित अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया। जांच में सामने आया कि ये मदरसे न तो मारकों पर खरे उतर रहे थे और न ही इनका पंजीकरण कराया गया था।

संपादकीय

‘जयचंदों’ को मिट्टी में मिलाएं

यकीनन

कश्मीर बदला है। पहलगाम में तो सड़कों पर और होटलों में सन्नाटा पसरा है। दुकानों पर ताले लटके हैं। लोग मानसिक तौर पर आहत हैं, क्योंकि कश्मीरियत के मेहमानों के कत्ल किए गए हैं। उनकी परंपराएं छिन्न-भिन्न हुई हैं। कश्मीर में सैलानियों को इस तरह कभी भी निशाना नहीं बनाया गया। कश्मीर के पेट पर लात मारी गई है। श्रीनगर के ऐतिहासिक ‘लाल चौक’ पर जो विरोध-प्रदर्शन किए गए, उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, डोगरा आदि सभी समुदायों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। डल लेक पर शिकारे बंद पड़े हैं और वे सामूहिक तौर पर आतंकवाद को खारिज कर रहे हैं। जिन हाथों में कभी पत्थर और ‘हिंदुस्तान विरोध’ की तख्तियां होती थीं, आज उन हाथों में ‘तिरंगा’ लहरा रहा है। कारगिल से कन्याकुमारी तक गुस्सा और आक्रोश एक जैसा ही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन यकीन दिलाता है कि आतंकवाद ने जब भी

मासूम, बेकसूर और निहत्थे लोगों की बर्बर हत्याएं की हैं, तब समूचा भारत एकसूत्र में बंधा दिखाई दिया है। तमाम विपक्षी दलों ने भी सरकार को, आतंकियों के खिलाफ, कोई भी कार्रवाई करने को अधिकृत किया है। सरकार और सुरक्षा-खुफिया तंत्र ने स्वीकार किया है कि सुरक्षा-व्यवस्था में चूक हुई है, लेकिन सर्वदलीय बैठक को ब्रीफ किया गया है कि कुछ दूर ऑपरेटर सैलानियों को बैसरन घाटी के घसियाले मैदान तक ले गए थे और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई, लिहाजा पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त भी नहीं किए जा सके। पहलगाम के अन्य हॉटस्पॉट के आसपास करीब 500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। वहां कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई है। यह सरकार के पक्ष की सफाई हो सकती है, लेकिन सर्वदलीय बैठक को ब्रीफ किया गया है कि कुछ दूर ऑपरेटर सैलानियों को बैसरन घाटी के घसियाले मैदान तक ले गए थे और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई, लिहाजा पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त भी नहीं किए जा सके। पहलगाम के अन्य हॉटस्पॉट के आसपास करीब 500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। वहां कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई है। यह सरकार के पक्ष की सफाई हो सकती है, लेकिन स्थानीय पुलिस को यह साफ दिख रहा होगा कि बैसरन में हजारों पर्यटक जा रहे हैं। पुलिस आंख नहीं मूंद सकती। बहरहाल अब हमें प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार पर भरोसा करना चाहिए कि आतंकियों और उनके आकाओं को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। आतंकियों की बची-खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक़्त आ गया है। देश की भावनाओं और उत्साह के महेनजर प्रधानमंत्री का ऐसा संबोधन भी बेहद जरूरी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ‘कश्मीर के जयचंदों’ को, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में, बड़ी बाधा मानते हैं। वे संख्या में भी काफी हैं और ताकतवर भी हैं। जब तक इन ‘जयचंदों’ को मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा, तब तक भारत आतंकवाद का समूल विनाश नहीं कर सकता। ये ‘जयचंद’ आतंकियों के स्थानीय गिरोह हैं, स्लीपर सेल हैं और पनाहगाह भी हैं। एक सूचना सामने आई है कि जो आतंकी ‘पहलगाम नरसंहार’ का सरगना था, वह बीते 4-5 साल से कश्मीर में सक्रिय है और कोने-कोने से वाकिफ है। स्थानीय खुफिया-तंत्र क्या करता रहा है? हम इस सूचना की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ‘आतंकियों के जयचंद’

राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, रेहड़ी-पटरी वाले कारोबारी के रूप में, सामाजिक अफवाह के तौर पर मौजूद और सक्रिय हैं, यह खुलासा तो सेवानिवृत्त सैन्य जनरल और पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, जिन्होंने अतीत के उग्र और हल्कारे आतंकियों के दौर देखे हैं और उनसे लड़ाई भी की है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ‘आतंकवाद के जयचंदों’ की पूरी सुचियां पुलिस और सेना के पास होती हैं। ‘जयचंदों’ का निचले स्तर तक जो जाल फैला है, उसकी सम्पक जानकारी होती है। सूचनाओं के आधार पर ये सुचियां तैयार की जाती हैं। इन पर कार्रवाई तभी होगी, जब राजनीतिक नेतृत्व ‘हरी झंडी’ देगा। रक्षा विशेषज्ञों की सूचनाओं के आधार पर पहले ‘जयचंदों’ को मिट्टी में मिलाया जाए।

कुछ

अलग

दिल देखो, बिल न देखो...

कौन

कहता है कि सरकार काम नहीं कर रही ? ऐसा कहने वालों को पहले अपने काले चश्मे उतारने चाहिए, वरना सरकार की पारदर्शिता कैसे दिखेगी ? सरकार जनहित में इतनी संवेदनशील है कि अफवाह की फुसफुसाहट भी होती है तो खुफिया तंत्र तुरंत उसे पकड़ लेता है और बिना आव-ताव देखे जांच बैठ जाती है। क्योंकि सरकार जनहित को लेकर पूरी तरह समर्पित है। न कुछ गलत देख सकती है और न बर्दाश्त कर सकती है। इससे सरकार की कमिटमेंट और कार्यक्षमता की झलक दुनिया को मिल जाती है। नेताजी को खिलाया गया मुर्गा जंगली था या बेचारा देसी टाइप का था, सरकार ने राष्ट्रीय मीडिया में यह मामला उछलते ही फौरन पुलिस को सक्रिय कर दिया। जिन्होंने सोशल मीडिया और अखबारों में शहीद हुए मुर्गों को जंगली मुर्गी का नाम दे दिया था, उन पर केस दर्ज हो गए। पब्लिक को पता चल गया कि सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। सरकार ने जांच बिठाई तो पता चला कि मुर्गा जंगली नहीं था। क्योंकि जंगली का जुगाड़ हो नहीं पाया था। क्योंकि जंगल में कोई जंगली मुर्गा बचा ही नहीं था। सब जान बचाकर धर-उधर के राज्यों में भाग गए थे। फिर समोसा प्रकरण हुआ। समोसा नेता जी की प्लेट तक क्यों नहीं पहुँचा और रास्ते में कौन लोग उस समोसे को खा गए, इस बारे बड़ी-बड़ी खबरे छपी तो फिर सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जांच बिठा दी। मामला फाइव स्टार समोसा और देसी हलवाई के समोसे के बीच उलझ कर रह गया। जांच रिपोर्ट आई और गइ। जनता में चर्चा शुरू हुई और फिर खत्म हुई। समोसा पेट से बाहर नहीं आया। होली के दिन एक और मामला सामने आया। कुछ सीनियर अफसरों ने

परिवार सहित नाच-गाना किया, भोज चरचा और जनता की आंखों में गुलाल झाँक कर जनता की खजाने से बिल ट्रेजरी में भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सरकार की इज्जत पर आंच आई। सरकार की फजीहत होने लगी तो सरकार ने फिर संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार जांच उन अफसर को नहीं बैठी जिन्होंने भोज किया था और बिल सरकार को प्रस्तुत कर दिया था, बल्कि उन पर बैठी जिन्होंने बिल लीक किया। यानी सरकारी खजाने से खाना-पीना तो जायज है, लेकिन बिल लिंक के सामने लीक कर देना बहुत बड़ा गुनाह है। अब लीक करने वालों पर एक्शन होगा। हो सकता है कि दो-चार बाबू सस्पेंड भी हो जाएं, क्योंकि सरकार संवेदनशील है। क्योंकि सरकार का रुख बहुत सख्त है। अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क है। सरकार सफेद मामलों में तो वाह-वाह ही लूटना चाहती है, लेकिन काले कारनामों पर पर्दा डाले रखना चाहती है। इसलिए फौरन जांच बिठा दी जाती है। कुछ महीने जांच चलती रहती है। फिर रिपोर्ट नेताजी के पास आती है। नेताजी के चलते के नीचे फाइलों की मोटी गहियां हैं। हर गद्दी में एक जांच रिपोर्ट सो रही है और नेताजी उन्हीं के ऊपर सोते हैं पूरी तसल्ली से। पब्लिक को फिर किसी नई जांच का ईंतजार रहता है और जांच पारंगत जांच के लिए किसी नए कारनामे का ईंतजार रहता है। सरकार में कारनामे करने वाले बहुत गणमान्य लोग हैं। उन्हें ऐसे कारनामे करने का लंबा अनुभव है और उनके इस अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें ऊँचे पदों पर भी बिठा रखा है। हर जांच एक सरकारी नाटक है जिसमें कलाकार पुराने हैं, संकट नई होती है। जनता दर्शक है। तालियां बजाती है और फिर भूल जाती है।

प्रमोद भार्गव

6

आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पांच बड़े कूटनीतिक प्रहार कर दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंधु जल समझौते को अनिघ्नित काल के लिए स्थगित करना है। यह एक ऐसी कूटनीतिक चाल है, जिससे पाकिस्तान को भीषण जलसंकट का सामना तो करना पड़ेगा ही आर्थिक समृद्धि में भी यह फैसला मटा घोलने का काम करेगा। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करते हुए उन्हें 48 घंटे में पाक लौट जाने का आदेश दिया है। अटारी-वाघा सीमा-द्वार बंद कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान से अपने सैन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। इन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ना होगा। ये सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा समिति (सीसीएस) की बैठक में लिए गए हैं। आतंकवादियों की शरणस्थली बने पाकिस्तान को ये कूटनीतिक सशक्त समय की जरूरत है। अमानुषिक दगाबाजी के आदि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के 'गले की नस' है। पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रचकर कश्मीर के अवाग की इसी आर्थिक श्वास की नली को अवरुद्ध कर दिया है। अब भारत ने पलटवार करते हुए सिंधु की जलधारा को अवरुद्ध करके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है। यदि यह जवाब बहुत पहले दे दिया गया होता तो शायद पाक से निर्यात आतंक के ये हथालत पनप ही नहीं पाते ? 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने का समझौता हुआ था। इस समझौते पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसके अंतर्गत पाकिस्तान से पूर्वी क्षेत्र की तीन नदियों व्यास, रावी व सतलुज की जल राशि पर नियंत्रण भारत के सुपुर्द किया गया था और पश्चिम की नदियों सिंधु, चिनाब व झेलम पर नियंत्रण की जम्मेदारी पाक को सौंपी गई थी। इसके तहत भारत के ऊपरी हिस्से में बहने वाली इन छह नदियों का 80.52 यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी पाकिस्तान को हर साल दिया जाता है। जबकि भारत के

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

26 से अधिक पर्यटक मारे गए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने यह हमला ऐसे समय में किया जब अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा और बच्चों के साथ भारत की यात्रा पर थे। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का निहितार्थ इस यात्रा में विघ्न डाल कर कश्मीर के मुद्दे पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना था। पाकिस्तान इस तरह के कुत्सित प्रयास पूर्व में भी कर चुका है। बेरोजगारी, भारी भरकम कर्जा और घरेलू आतंकवाद से त्रस्त पाकिस्तान ने इन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वेन्स की यात्रा के दौरान हमला करवाने के समय का चुनाव किया। अमरीका सहित विश्व के तकररीब सभी देशों ने इस हमले की तीखी निंदा की। सवाल यही है कि क्या अमरीका सिर्फ निंदा तक ही सीमित रहेगा। पूर्व में भी इसी तरह के पाक प्रायोजित हमले के दंश भारत झेलता रहा है। जब

कश्मीर

के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पांच बड़े कूटनीतिक प्रहार कर दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंधु जल समझौते को अनिघ्नित काल के लिए स्थगित करना है। यह एक ऐसी कूटनीतिक चाल है, जिससे पाकिस्तान को भीषण जलसंकट का सामना तो करना पड़ेगा ही आर्थिक समृद्धि में भी यह फैसला मटा घोलने का काम करेगा। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करते हुए उन्हें 48 घंटे में पाक लौट जाने का आदेश दिया है। अटारी-वाघा सीमा-द्वार बंद कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान से अपने सैन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। इन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ना होगा। ये सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा समिति (सीसीएस) की बैठक में लिए गए हैं। आतंकवादियों की शरणस्थली बने पाकिस्तान को ये कूटनीतिक सशक्त समय की जरूरत है। अमानुषिक दगाबाजी के आदि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के 'गले की नस' है। पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रचकर कश्मीर के अवाग की इसी आर्थिक श्वास की नली को अवरुद्ध कर दिया है। अब भारत ने पलटवार करते हुए सिंधु की जलधारा को अवरुद्ध करके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है। यदि यह जवाब बहुत पहले दे दिया गया होता तो शायद पाक से निर्यात आतंक के ये हथालत पनप ही नहीं पाते ? 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने का समझौता हुआ था। इस समझौते पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसके अंतर्गत पाकिस्तान से पूर्वी क्षेत्र की तीन नदियों व्यास, रावी व सतलुज की जल राशि पर नियंत्रण भारत के सुपुर्द किया गया था और पश्चिम की नदियों सिंधु, चिनाब व झेलम पर नियंत्रण की जम्मेदारी पाक को सौंपी गई थी। इसके तहत भारत के ऊपरी हिस्से में बहने वाली इन छह नदियों का 80.52 यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी पाकिस्तान को हर साल दिया जाता है। जबकि भारत के

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

दृष्टि

कोण

आतंकवाद पर अमरीका का ढुलमुल रवैया

कभी भी ऐसे हमले हुए हैं, अमरीका ने सिर्फ घडियाली आंसू ही बहाए हैं। सही मायने में तो अमरीका चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान पर ऐसी आतंकी वारदातों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करे। यही वजह है कि अन्य देशों की तरह अमरीका भी सिर्फ सहानुभूति जता कर अपनी जम्मेदारी पूरी कर लेता है। अमरीका बेशक इन हमलों के लिए एस सीएसटीए नही हो, किंतु पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य रिश्ते कहीं न कहीं आतंकवाद को प्रोत्साहित करते नजर आते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब किसी अमरीकी विशिष्ट व्यक्ति के भारत दौरे के दौरान आतंकी वारदात हुई है। 120 मार्च 2000 की रात को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के अन्ननाग जिले के चिट्ठीसिंहपोरा गांव में 36 सिख ग्रामीणों का नरसंहार किया था। यह घटना अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की 21- 25 मार्च की यात्रा से ठीक पहले हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने

क्लिंटन के सामने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का मुद्दा उठाया था। उस समय क्लिंटन जबपुर और आगरा के दौरे पर थे, जबकि विदेश मंत्री मेडलिन अलबाइट और उप विदेश मंत्री स्टोब टैलबोट भारतीय अधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिल्ली में ही थे। वर्ष 2002 में जब दक्षिण एशियाई मामलों को लेकर अमरीकी अस्सिस्टेड सेक्रेटरी क्लिस्टीनी का दौरा भारत की यात्रा पर थीं, तब 14 मई 2002 को जम्मू-कश्मीर के कालूचक के पास एक आतंकवादी हमला हुआ। तीन आतंकवादियों ने मनाली से जम्मू जा रही हिमाचल रोडवेज की बस पर हमला किया और सात लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद आतंकी आर्मी क्वाटर्स में घुस गए और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 10 बच्चों, आठ महिलाओं और पांच सैन्यकर्मियों सहित 23 लोग मारे गए। मारे गए बच्चों की उम्र वार से 10 साल के बीच थी और इस हमले में कुल 34 लोग घायल हुए थे। इन आतंकी हमलों से जाहिर है कि

पाकपरस्त आतंकियों ने हमला करने के लिए ऐसे वक़्त का चुनाव किया जबकि कोई न कोई प्रमुख अमरीकी भारत यात्रा पर आया हो। आश्चर्य की बात यह है कि इन हमलों के बावजूद अमरीका ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की। कहने को अमरीका भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताता है, किंतु हकीकत में उसका उद्देश्यसिर्फ व्यावसायिक हित साधना भर रहा है। अमरीका के व्यावसायिक हित सर्वोपरि हैं। भारत के भारी विरोध के बावजूद अमरीका ने पाकिस्तान को घातक एफ-16 लाइट फ़ायिंग मिमानों की बिक्री की। इतना ही नहीं, इनकी मरम्मत के नाम पर लाखों डालर की मदद भी अमरीका करता रहा है। अमरीका ने भारत के विरोध को नजरअंदाज करते हुए यह सैन्य मदद दी। अमरीका न सिर्फ भारत से दुश्मनी साधे हुए पाकिस्तान की हरसंभव मदद करता रहा है, बल्कि विदेशी धरती से भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों और देशों का सहयोग भी करता

रहा है। कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में अमरीका ने कनाडा की पैरवी की। कनाडा फाइव आईज का सदस्य है। फाइव आईज में कनाडा के अहम सहयोगी अमरीका ने पिछले साल निज्जर हत्याकांड में भारतीय एजेंट्स की कथित संलिप्तता के कनाडा के आरोपों पर टिप्पणी की। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्टी म्लिर ने कहा था कि हमने साफ कर दिया है कि कनाडा के आरोप बेहद ही गंभीर हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम चाहते थे कि भारत कनाडा की जांच में सहयोग करे, लेकिन भारत सहयोग नहीं कर रहा। इसके बजाय भारत ने एक वैकल्पिक रास्ता चुना है। इतना ही नहीं, अमरीका से भारत को आतंकी कार्रवाई की धमकी देने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी। इस पर भी अमरीका ने जानबूझ कर नकेल नहीं कसी।

कुछ

अलग

देश

दुनीया से

संधि का स्थान प्रदेश के विकास का आधार

पहलगाम

हमले के विरोध में भारत सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर जो कदम उठाए हैं, उनमें वर्ष 1960 में भारत-पाक के बीच वलड बैंक द्वारा व्यवस्थित सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल है। भारत सरकार के इस निर्णय से हालांकि शुरुआती दौर में तो पाकिस्तान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर भारत इस संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से आई नदियों के जल प्रवाह की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक आधारभूत ढांचे का निर्माण कर लेता है, तो उत्तर भारत में खुशहाली की नई इबारत तो लिखी जाएगी ही, साथ में पाकिस्तान की लगभग 21 करोड़ की जनसंख्या सीधे तौर पर प्रभावित होगी जो पाकिस्तान को हमेशा के लिए घुटनों पर लाने के लिए काफी है। भारत सरकार अगर अपने इस निर्णय पर अडिग रहती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो सकता है। आज से 9 वर्ष पूर्व इसी विषय पर ‘दिव्य हिमाचल’ के संपादकीय में स्पष्ट लिखा था और कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ हुई इस गलत संधि से पीछे हट जाता है तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद समेत कई समस्याओं का पूर्ण रूपेण सफ़या हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 9 वर्षों की बातचीत के पश्चात 19 सितंबर 1960 को कराची में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण मिला था, वहीं पाकिस्तान को झेलम, चेनाब और सिंधु नदी पर अधिकार मिला, हालांकि भारत पश्चिमी नदियों के भारत में बहने के दौरान कुछ हिस्से का कुल जल मात्रा में उपयोग कर सकता था, परंतु यह कमोबेश पाकिस्तान की मर्जी पर ही निर्भर था। इस संधि को इसलिए भी भेदभावपूर्ण और गलत माना जाता रहा है क्योंकि इस संधि में भारत के हिस्से आई तीनों नदियों का कुल जल प्रवाह 41000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड है, वहीं आखिरी सिंधु नदी का जल प्रवाह 233000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत को इस समझौते से 30 फीसदी, तो पाकिस्तान को कुल 70 फीसदी पानी मिला और सबसे ज्यादा अपमानजनक पहलू तो यह था कि भारत को इस संधि की अनुसार 125 मीट्रिक टन सोना अथवा 6 करोड़ 20 लाख पारंगत पाकिस्तान को देने के लिए बाध्य किया गया और भारत की कमजोरी देखिए कि 1965 के युद्ध के बावजूद भारत ने दस वार्षिक किस्तों में कहा धनराशि पाकिस्तान को दी। इसे भारतीय नेतृत्व की कमजोरी ही कहा जाएगा कि युद्धों के बाद भी इस संधि को नहीं तोड़ा गया। इस संधि के टूटने से पाकिस्तान पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। कृषि आधारित उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। पहले से ही कई तरह की आंतरिक समस्याओं में उलझा पाकिस्तान इस झटके को सहन करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान ने शायद सोचा ही नहीं था कि भारतीय नेतृत्व कभी इस हद तक जा सकता है। तीन युद्धों के पश्चात भी इस संधि के न टूटने को पाकिस्तान ने इसे भारतीय नेतृत्व की कमजोरी मान लिया था



हिस्से में महज 19.48 प्रतिशत पानी ही शेष रह जाता है। नदियों की ऊपरी धारा (भारत में बहने वाला पानी) के जल-बंटवारे में उदारता की ऐसी अनूठी मिसाल दुनिया के किसी भी अन्य जल-समझौते में देखने में नहीं आई है। इसीलिए अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों से संबंधित समिति ने 2011 में दावा किया था कि यह संधि दुनिया की सफलतम संधियों में से एक है। लेकिन यह संधि केवल इसलिए सफल है, क्योंकि भारत संधियों की शर्तों को निभाने के प्रति अब तक उदार एवं प्रतिबद्ध बना हुआ है। जबकि जम्मू-कश्मीर को हर साल इस संधि के पालन में करीब 60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत की भूमि पर इन नदियों का अकूत जल भंडार होने के बावजूद इस संधि के चलते इस राज्य को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई इन्हीं नदियों के जल से होती है। पाक के बड़े भू-भाग की 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल की जरूरतें इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं। यह संधि लंबे समय तक स्थगित रहती है तो पाकिस्तान में अकाल और सूखे के हालात बन सकते हैं। दरअसल सिंधु-संधि के तहत उत्तर से दक्षिण को बांटने वाली एक रेखा सुनिश्चित की गई है। इसके तहत सिंधु क्षेत्र में आने वाली तीन नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम पूरी तरह पाकिस्तान को उपहार में दे दी गई हैं। इसके उलट भारतीय संभुता क्षेत्र में आने वाली व्यास, रावी व सतलुज नदियों के बचे हुए हिस्से में ही जल सीमित रह गया है। इस लिहाज से यह संधि दुनिया की ऐसी इकलौती अंतरदेशीय जल संधि है, जिसमें सीमित संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है और संधि की असमान शर्तों के चलते ऊपरी जलधारा वाला देश नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा वाले देश पाकिस्तान के लिए अपने हितों की न केवल अनदेखी करता है, वरन बालिदान कर

देता है। इतनी बेजोड़ और पाक हितकारी संधि होने के बावजूद पाक ने भारत की उदार शालीनता का उत्तर पूरे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में आतंकी हमलों के रूप में तो दिया ही, अब इनका विस्तार भारतीय सेना व पुलिस के सुरक्षित ठिकानों तक भी किया हुआ है। अब पर्यटकों की हिंदू धार्मिक पहचान करके जो नरसंहार पहलगाम की बैसरन घाटी में किया है, वह यह जताने के लिए काफी है कि हमला धर्म के आधार पर किया गया है। ये सभी हमले आतंकवाद को बहाना बनाकर छद्म युद्ध के जरिए किए गए, जबकि ये सभी हमले पाक सेना की करतूत हैं। दरअसल छद्म युद्ध में लागत तो कम आती है, हमलावर देश पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर इस बहाने रक्षात्मक भी हो जाता है कि इन हमलों में उसका नहीं, आतंकवादियों का हाथ है। बावजूद हैरानी इस बात पर है कि इस संधि को तोड़ने की हिम्मत न तो 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद दिखाई गई और न ही 1971 में ? हालांकि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को टुकड़ों में विभाजित कर नए राष्ट्र बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने की बड़ी कूट व रणनीतिक सफलता हासिल की थी। कारगिल युद्ध के समय भी हम इस संधि को तोड़ने से चुके हैं। देर से ही सही इस संधि को तोड़ने की पहल देशहित में है। दरअसल पाकिस्तान की प्रकृति में ही अहसासफरोसी शुभारंभ है। इसीलिए भारत ने जब झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर बनने वाली ‘किशन गंगा जल विद्युत परियोजना’ की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान ने बुनियाद रखते ही नीदरलैंड में स्थित ‘अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय’ में 2010 में ही आपर्ति दर्ज करा दी थी। जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले में किशनगंगा नदी पर 300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। हालांकि 20 दिसंबर 2013 को इसका फैसला भी हो गया। दुर्भाग्य कहलें या भारत द्वारा ठीक से अपने पक्ष की पैरवी नहीं करने के कारण यह निर्णय भारत के व्यापक हित साधे रखने में असफल रहा है। न्यायालय ने भारत को परियोजना निर्माण की अनुमति तो दे दी, लेकिन भारत को बाध्य किया गया कि वह ‘रन ऑफ दि रिवर’ प्रणाली के तहत नदियों का प्रवाह निरंतर जारी रखे। फैसले के मुताबिक किशनगंगा नदी में पूरे साल हर समय 9 क्यूसेक मीटर प्रति सेकंड का न्यूनतम जल प्रवाह जारी रहेगा। हालांकि पाकिस्तान ने अपील में 100 क्यूसेक मीटर प्रति सेकंड पानी के प्राकृतिक प्रवाह की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने नहीं माना।

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले

जो जिस भाषा में समझेगा, उसी भाषा में जवाब देगा भारत : योगी

मुख्यमंत्री ने नाव पर बैठकर देखा शारदा नदी के चैनलाइजेशन का कार्य, 10 जून तक कार्य पूरा करने का निर्देश

लखीमपुर खीरी (हिस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। भारत सरकार का सेवा, सुरक्षा व सुशासन का मॉडल विकास, गरीब कल्याण और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत *जिस भाषा में समझेगा, उस भाषा में जवाब देने के लिए* नया भारत तैयार है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छोड़ेगा भी नहीं। जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत ही यूपी को माफिया, अराजकता, दंगा मुक्त किया और देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में लाकर खड़ा किया। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को लखीमपुर खीरी में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान, आवास व ट्रैक्टर के लाभार्थियों के आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्टीमर में बैठक बाद नियंत्रण के लिए किए गए कार्य का मुआयना भी किया।



उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष पलिया व निधासन क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से जूझते हुए देखा था, तब मैंने कहा था कि चिंता न कीजिए। इसके स्थायी समाधान का रास्ता निकालेंगे। जमप्रतिनिधियों के सहयोग से जलशक्ति विभाग बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए शारदा नदी को चैनलाइज करने जा रहा है। इससे किसान का खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। सात किमी. लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने कहा कि पहले काम शुरू करो। अब यह कार्य तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश बताते

हुए कहा कि बाढ़ हो या बीमारी, नए भारत का नया उग्र इसके समाधान के लिए बखूबी आगे बढ़ा है। योगी ने कहा कि सरकार जो पैसा खर्च करती है, वह मुख्यमंत्री-मंत्री का नहीं, बल्कि यह जनता के टैक्स का पैसा है। इसका सदुपयोग होना चाहिए। पहले प्रस्ताव आया था कि 180 करोड़ से तटबंध बनाया जाए। इससे किसानों की जमीन भी जाती। मैंने पूछा कि शारदा नदी में तीन-सवा तीन लाख क्यूसेक पानी आएगा तो मिट्टी का तटबंध कैसे इसे रोक पाएगा। यह समस्या का समाधान नहीं है। नदी को चैनलाइज कीजिये, ड्रेजर मंगाइये और नदी को एक साथ चलने का रास्ता दीजिये, तब

था। इस दौरान जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, विधायक हरविंदर कुमार उर्फ रोमी साहनी, विनोद शंकर अवस्थी, अमन गिरि, लोकेंद्र प्रताप सिंह, योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, शशांक वर्मा, सौरभ सिंह सोनू, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, कमिश्नर रोशन जैकब, जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल आदि मौजूद रहीं। सीएम योगी ने भोलेराम, बालचंद्र, पृथ्वी लाल को ट्रैक्टर व मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी सनेव, मीना देवी, नीतू, कुसुमा, रीमा को आवासों की चाबी दी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 358 समूहों को रिवाल्विंग फंड तथा 882 समूहों को सीआईएफ का डेमो चेक (14 करोड़, 30 लाख, 40 हजार) दिया गया। यह चेक सुनीता देवी, रेनु, अर्चना, शबाना, रंजू देवी ने प्राप्त किया। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थी अहिरथा राणा, वैशाली दिवाकर, हिमांशु जायसवाल, विनीत कुमार पटेल और रचित अग्रवाल को सीएम ने चेक प्रदान किया।

वन नेशन वन इलेक्शन से बड़ेगी भारत की जीडीपी : नीरज सिंह



लखनऊ (हिस)। *वन नेशन वन इलेक्शन* अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सुभाष गर्लस डिग्री कॉलेज अलीगंज में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के तौर पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि *वन नेशन वन इलेक्शन* से भारत की जीडीपी बढ़ेगी। उन्होंने कहा जब तक 140 करोड़ भारतीय एक दिशा में एक लक्ष्य निर्धारित करके नहीं चलेंगे तब तक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा नहीं किया जा सकता। कई राजनीतिक दलों ने अपने संकीर्ण

मानसिकता के कारण इस परिवर्तन को नहीं होने दिया। पूरे चुनाव का पैटर्न जो आजाद भारत के अंदर था हर 5 साल में चुनाव होंगे उसे जो पूरे पैटर्न को बदलने का काम हमारे उस समय के राजनीतिक दलों ने किया । नीरज सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव, विधान सभा का चुनाव, नगर निकाय के चुनाव व पंचायत चुनाव अलग-अलग होते हैं। इससे चुनाव कराने में खर्चा अधिक लगता है। अगर हम केवल एक चुनाव कर दें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी और जो हमने कल्पना की है एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर कालेज की प्रिंसिपल रश्मि विस्नोई, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अनुभव द्विवेदी, युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मानदेन्द्र प्रताप सिंह, नगर उपाध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल, महानगर मीडिया प्रभारी निखिल उपाध्याय, अभियान संयोजक अमित त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, पार्षद स्वदेश सिंह, युवा मोर्चा महामंत्री अभीषेक गुप्ता, उपाध्यक्ष सौरभ तिवारी, अतुल सिंह, सचिन सोनकर, समर्थ सिन्हा की उपस्थिति रही।

शहर में भीषण पेयजल संकट लोगों ने किया जोधपुर- जयपुर हाईवे जाम, लगी वाहनों की कतारें



जोधपुर (हिस)। शहर में बढ़ती गर्मी और इंदिरा गांधी नहर क्लोजर के बाद हर वर्ष पेयजल संकट गहरा जाता है। मगर जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है। इस बार भी यह ही हाल शहर और आस पास के गांवों का हो रहा है। जलदाय विभाग लाख दावें कर रहा है पेयजल संकट नहीं आएगा। मगर विगत पंद्रह दिनों में शहर में पानी को लेकर त्राहि- त्राहि मची हुई है। शहर के कई इलाके पेयजल संकट से बुरी तरह गुजर रहे हैं। आज सुबह जोधपुर जयपुर हाइवे पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला पानी की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। हाइवे को जाम कर दिया। आने जाने वाले वाहन रूक गए। जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। विरोध स्वरूप महिलाएँ भी सड़क पर उतरीं और मटकियाँ फोड़कर प्रदर्शन किया। शहर में गर्मी की दस्तक के साथ ही पेयजल आपूर्ति में कटौती करनी जलदाय विभाग ने शुरू कर दी और महिने में घोषित चार दिन और अघोषित छह दिन की कटौती के चलते पेयजल की समस्या गहराती जा रही है। दूसरी तरफ जलदाय विभाग और डिस्कॉम की मिलीभगत कहे या शहरवासियों का दुर्भाग्य कि पेयजल आपूर्ति के समय अधिकांश क्षेत्रों में बिजली कटौती भी हो रही है। आज सुबह भी बनाड़ क्षेत्र में पेयजल की अनियमित सप्लाई से परेशान लोगों के सब्र का प्याला छलक उठा और उन्होंने जोधपुर जयपुर हाईवे पर ही रास्ता जाम कर दिया। अचानक हुए रास्ता जाम की घटना से इस मुख्य सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लम्बी कतारें लग गईं। पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के प्रयास कि ए। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं और क्षेत्रवासियों ने सड़क पर जमकर मटकियां फोड़कर आक्रोश भी व्यक्त किया।

योगी सरकार में सुदृढ़ हो रहे नदियों के तटबंध, बाढ़ से बचेंगे गांव

योगी सरकार ने राप्ती, रोहिन, घाघरा, कुआनो और गुरा नदियों के तटबंध पर कराए हैं कार्य

गोरखपुर (हिस)। दशकों तक बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए अभिशप्त रहे गोरखपुर को बाढ़ बचाव के लिए संवेदनशील योगी सरकार की समयबद्ध कार्ययोजना का सकारात्मक परिणाम साल दर साल दिख रहा है। 2017 के बाद से लगातार हो रहे बाढ़ सुरक्षा के कार्यों से नदियों के तटबंध सुरक्षित होते गए और जिले में होने वाली व्यापक हानि में अभूतपूर्व कमी आई है। योगी सरकार में नदियों के तटबंधों को सुरक्षित करने का सिलसिला लगातार जारी है और इससे बड़े पैमाने पर गांवों को बाढ़ की त्रासदी से बचाने में कामयाबी मिली है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी बाढ़ की दस्तक से काफी पहले ही गोरखपुर में 119 करोड़ रुपये से अधिक की बाढ़ बचाव परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। आगामी दिनों में इन कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों संभावित है।



गोरखपुर में बाढ़ खंड, बाढ़ खंड-2 और ड्रेनेज खंड ने कुल मिलाकर बाढ़ सुरक्षा की 27 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विकास सिंह के अनुसार ये परियोजनाएँ राप्ती, रोहिन, घाघरा, गुरा, कुआनो नदियों के तटबंधों और इन तटबंधों के आसपास बसे गांवों को मानसून में बाढ़ की त्रासदी से बचाने की हैं। इन परियोजनाओं का लाभ जिले की सात

विधानसभा क्षेत्रों गोरखपुर ग्रामीण, चौरौचौरा, खजनी, बांसगांव, सहजनवां, कैं पियरगंज और चिल्लूपार की जनता को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ सालों से गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति पर काफी नियंत्रण पा लिया गया है। जबकि एक लंबे समय तक बाढ़ की बसे गांवों को चैनलाइज कराया, बड़े गांवों की प्रलयंकारी बाढ़ तो आज भी लोगों को याद है। बाढ़ पर

काबू पाने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अपने संसदीय कार्यकाल से ही वह जिले में आने वाली बाढ़ से वाक़िफ थे। लिहाजा मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कार्ययोजना बनवाकर जहां जरूरत हुई वहां नदियों को ड्रेजिंग कराई, नदियों की धारा को चैनलाइज कराया, बड़े पैमाने पर बंधों पर बोल्ट्ड पिचिंग के काम कराए।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भीम सेना अध्यक्ष को मिली गोली मारने की धमकी

गुरुग्राम (हिस)। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से गुरुग्राम निवासी व भीम सेना अध्यक्ष सतपाल तंवर को गोली मारने की धमकी मिली है। सतपाल तंवर ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर ने सतपाल तंवर की पत्नी से भी फोन पर बदतमीजी की है। कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस सतर्क हो गई। गुरुग्राम के गांव खांडसा निवासी व भीम सेना के अध्यक्ष सतपाल तंवर ने पुलिस को एक शिकायत देकर कहा है कि बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती पर वह मुंबई में था। इसी दौरान उसके गुरुग्राम कार्यालय पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम ओ किसी ने फोन करके उसे गोली मारने की धमकी दी है। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर बताया। तंवर के मुताबिक फोन उठाने पर उसकी पत्नी के साथ भी



बदतमीजी की गई और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। शनिवार को थाना सेक्टर 37 के प्रभारी ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के संबंध में सतपाल तंवर का कहना है कि उसे कई बार फोन आ चुका है और अपवॉर्डमेंट लेकर गोली मारने की धमकी का शूट रहा है।

भारत-पाक सीमा पर फेंसिंग पार की जमीनों से दो दिन में फसल काटने के निर्देश

चंडीगढ़ (हिस)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हुई सख्ती ने पंजाब के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने शनिवार को पंजाब के सीमावर्ती गांवों में मुनदी कराते हुए कहा है कि सीमा पार फेंसिंग के पार खेतों की फसल 24 घंटे के भीतर काट लें। रविवार शाम को गेट बंद कर दिए जाएंगे। गुरुद्वारों से आज दिनभर ऐसी ही अनाउसमेंट होती रही। आज इस ऐलान को लेकर आज पूरे

दिन किसानों में अफरा-तफरी मची रही। हालांकि बीएसएफ की तरफ से इस संबंध में अधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दरअसल पंजाब के अमृतसर, तरनातार, गुरदासपुर, फिरोजपुर व फाजिल्का जिलों में बहुत से गांव ऐसे हैं, जिनके किसानों की आधी जमीन भारत और आधी पाकिस्तान में आती है। यह किसान रोजाना बीएसएफ के साथ फेंसिंग पार खेती के लिए जाते हैं। इन

किसानों के रोजाना आठ घंटे बार्डर पर ले जाया जाता है। इसी दौरान तीन दिन पहले किसानों के साथ गए बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान के सैनिकों ने हिंसत में ले लिया है। फ्लैग बैठक के बावजूद जवान को अभी तक जिले की बात करें तो यहां को 2500 एकड़ जमीन फेंसिंग पार है। अजनाला ने कहा कि फसल तो 80 फीसदी कट गई है लेकिन तड़ी (भूसा) बनाने के लिए नाड़ अभी खेतों में खड़ी है। उनका कहना है कि इस फरमान से

अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का में बार्डर से लगी तार के पार 22, 000 एकड़ खेती योग्य जमीन है। इसमें से 90 फीसदी पार खेती होती है। अमृतसर जिले की बात करें तो यहां को 2500 एकड़ जमीन फेंसिंग पार है। अजनाला ने कहा कि फसल तो 80 फीसदी कट गई है लेकिन तड़ी (भूसा) बनाने के लिए नाड़ अभी खेतों में खड़ी है। उनका कहना है कि इस फरमान से

किसान तूट्टी नहीं बना सकेगा। बार्डर एरिया सघर्ष कमेट्री के प्रधान डॉ. रतन सिंह रंथावा ने बताया कि सरकार ने भले ही यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया है, लेकिन इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रगहां के जिला प्रधान कश्मीर सिंह ने बताया कि हमारा भले ही नुकसान हो लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।

होटल में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने मारी रेड : चालीस युवक-युवतियां गिरफ्तार

जयपुर (हिस)। बगरू थाना थाना इलाके में शुक्रवार-शनिवार की मध्यरात्रि को पुलिस ने कारंवाई करते हुए एक होटल में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी करते हुए चालीस युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कारंवाई के दौरान बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। इसके अलावा होटल संचालक को भी शराब परोसते गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि बगरू थाना थाना इलाके में शुक्रवार-शनिवार की मध्यरात्रि को सूचना मिली थी कि इलाके के हिम्मतपुर स्थित होटल कैपलम अथवा पैलेस एंड रेस्टोरेंट में रेव पार्टी चल रही है। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को सावा वर्दी में मौके पर भेज कर तस्दीक कराई गई। जहां पुलिसकर्मियों के इशारा मिलने पर रात डेढ़ बजे बगरू और बिंदायका थाने का जाब्ता मौके पर भेजा गया। जहां पुलिस कारंवाई के दौरान बड़ी संख्या में युवक-युवती नशे की हालत में मिले तो कुछ पुलिस को देखकर भागने का प्रयास



करने लगे। जिन्हे पकड़ कर पूछताछ की गई और साथ ही होटल संचालक को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने होटल संचालक से शराब परोसने संबंधित आबकारी के दस्तावेज मांगे गए। लेकिन संचालक दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके बाद होटल संचालक मुकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। वहीं होटल में चल रही रेव पार्टी के दौरान

सोयब निवासी शास्त्री नगर, रोनक निवासी वैशाली नगर, लोकेश निवासी सवाई माधोपुर, मोहरसिंह निवासी सांगनेर, मुकेश शर्मा निवासी बगरू, प्रदीप सुराण निवासी बीकानेर, नवीन सैनी निवासी झुझुनू, चन्द्रप्रकाश गर्ग निवासी सवाई माधोपुर, अनिल कैडिया निवासी महेश नगर, सतीश सैनी निवासी महेशनगर, शैलेन्द्र गोयल निवासी बारां,

आशिष खंडेलवाल निवासी कोटा, सिराजुद्दीन निवासी शास्त्रीनगर, आशिष शर्मा निवासी बगरू, निखिल माहेस्वरी निवासी यूपी, साबीर निवासी शास्त्रीनगर, राजेन्द्र कुमार निवासी शाहपुर, भागीरथ कुमार निवासी कोटपुतली, सुनील निवासी भोलवाड़ा, विकास खंडेलवाल निवासी कोटा, रामनिवासी निवासी मुरलीपुरा, महिपाल निवासी नागौर, बनवारी लाल निवासी झोटवाड़ा, जितेन्द्र कुकरेजा निवासी कोटा, राहुल स्वामी निवाी कालवाड़, रामसिंह निवासी झुझुनू, रामप्रकाश निवासी मुहाना, मंजित सैनी निवासी सवाई माधोपुर, महेन्द्र सैनी निवासी सवाई माधोपुर, विष्णु रैगर निवासी अजमेर, मुल्लीभर निवासी टोंक, सोहन शर्मा निवासी बगरू, गिरांज सैनी निवासी मानसरोवर, भोलानाथ शर्मा निवासी ज्योतिनगर, मोहनलाल शर्मा निवासी बगरू, रणजीत सिंह निवासी वैशाली नगर, नरपतराम निवासी नागौर और कपिल निवाी कोटा को गिरफ्तार किया गया। सभी लोगों को बिंदायका थाने में रखा गया है।

बीजा रद होने के बाद एक भी पाकिस्तानी बिहार में नहीं रहेगा, शीघ्र कारंवाई होगी : सम्राट चौधरी



पटना (हिस)। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ देने को कहा गया है और यह समय सीमा कल 27 अप्रैल को समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, उनकी पहचान कर ली गई है और जरूरत पड़ी तो उन्हें

डिपोर्ट किया जाएगा। बीजा रद होने के बाद किसी पाकिस्तानी के यहां रहने का कोई उपाय नहीं, जो नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कारंवाई होगी। चौधरी ने कहा कि पहलगाम की आतंकी हिंसा भारत पर हमला है। दुख और आक्रोश के इस समय में पूरा देश एकजुट है। इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के आकाओं को मिट्टी में मिला देने का कड़ा संकल्प ले लिया है, तो उसे पूरा करने में बिहार हर कदम पर साथ खड़ा रहेगा। चौधरी ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने पहलगाम नरसंहार में अपनी नापाक सत्तिपत्ता स्वीकार करने के बजाय भारत से टकराव का रुख अपनाया और पिछले युद्ध के बाद हुआ शिमला समझौता रद कर दिया है, तो यह अच्छा ही है। अब भारत उनकी सीमा में घुसकर बदला लेगा।

जोधपुर में भगवा ध्वज का अपमान देवता चित्रित ध्वज को पैरों से रौंदा, बाजार बंद

जोधपुर (हिस)। शहर में शुक्रवार को मोती चौक क्षेत्र में इजराइल झंडे के अपमान के बाद एक बार फिर चिनीनी करतूत समाज विशेष के व्यक्ति द्वारा की गई है। इससे भीतरी शहर का माहौल तनावपूर्ण बन गया है। गर्मीए माहौल के बीच व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। शहर के के अंदरूनी क्षेत्र चोड़ों का चौक में आज सुबह माहौल गर्मा गया है। भगवा अथवा देवता चित्रित एक झंडे को समाज विशेष के व्यक्ति ने अपने पैरों तले रौंद दिया। जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। इस घटनाक्रम को लेकर भीतरी शहर में अब माहौल गर्माया हुआ है। दरअसल चोड़ों का चौक बर्द्धमान अस्पताल रोड पर आज सुबह माहौल गर्मा गया। बताया गया कि क्षेत्र में रहने वाले एक बंगाली सुनार शेख इशराफुद्दीन ने भगवा ध्वज जोकि देवता चित्रित था। उसे अपने पैरों तले रौंदने के साथ मसल दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो चोड़ों में समस्त व्यापारीगण एकत्र हो गए और विरोध जताने लगे। व्यापारियों ने तत्काल बाजार बंद कर दिया और बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बिगड़ते माहौल के बीच भारी पुलिस बल को लगाया गया। इधर माहौल बिगड़ने के बीच ही बंगाली सुनार शेख इशराफुद्दीन ने सोजीती गेट पुलिस चौकी की शरण ले ली और पब्लिक से अपना बचाव कर डाला। व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश नजर आया और वे कारंवाई की मांग करने लगे। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। बता दें कि शुक्रवार को भी सीसीटीवी फुटेज और फोटो वायरल हुए थे।



जेनसोल के खिलाफ इरेडा ने दर्ज कराई शिकायत दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट

नई दिल्ली

संकट में फंसी जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन फाइनेंसिंग के लिए कर्ज देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) ने कंपनी और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ अनुबंध उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई है।

इरेडा ने कहा कि जेनसोल के प्रवर्तकों ने

उनकी मंजूरी के बिना अपनी शेयरहोल्डिंग घटाई, जो सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। इरेडा ने 24 अप्रैल को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि जेनसोल के हालिया घटनाक्रमों के महेनजर आंतरिक समीक्षा शुरू की गई है और आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

हालांकि, इरेडा ने स्पष्ट किया कि जेनसोल का कर्ज खाता अभी एनपीए घोषित नहीं हुआ है। इस मामले की बारीकी से जांच

की जा रही है और समीक्षा के आधार पर आगे वसूली के कदम उठाए जाएंगे।

ईडी ने तेज की कार्रवाई

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी जेनसोल इंजीनियरिंग और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत दिल्ली, गुरुग्राम और अहमदाबाद में कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की गई और सह-प्रवर्तक पुनीत सिंह जग्गी को दिल्ली के एक

होटल से हिरासत में लिया गया। यहां बताया चलें कि कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के हेरफेर के आरोपों के चलते कंपनी के प्रवर्तक अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी जांच के घेरे में हैं। इस घटनाक्रम का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। शुक्रवार को जेनसोल इंजीनियरिंग के शेयर 4.96 फीसदी गिरकर 91.05 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले 52 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। वहीं, इरेडा के शेयर भी 4.40 फीसद टूटकर 167.40 रुपये पर बंद हुए।

न्यूज ब्रीफ

चोलामंडलम इनवेस्टमेंट का शानदार मुनाफा, गोल्ड लोन बिजनेस में उतरने की तैयारी



नई दिल्ली। चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने मार्च 2025 तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1,058 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह मुनाफा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 24 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त वर्ष 2024 की मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 853 करोड़ रुपये था। कंपनी ने एलान किया है कि वह जल्द ही गोल्ड लोन बिजनेस में भी कदम रखेगी। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 1,541.20 रुपये पर बंद हुए। मार्च तिमाही में कंपनी की नेट इंटरैस्ट इनकम 30.8 प्रतिशत बढ़कर 2,006.9 करोड़ रुपये रही। इसी अवधि में कुल डिस्बर्समेंट्स 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 24,784 करोड़ रुपये पर पहुंच गए, जो एक साल पहले 21,020 करोड़ रुपये थे। चोलामंडलम का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 31 मार्च 2025 तक 1.53 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो सालाना आधार पर 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

ओसामु सुजुकी की याद में होगी ओएससीआई सेंटर की स्थापना



नई दिल्ली। भारत में जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ओसामु सुजुकी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (ओएससीआई) स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है। दिल्ली के यशोभूमि में एक स्मरण समारोह के दौरान यह घोषणा की गई, जिसमें स्वर्गीय ओसामु सुजुकी को श्रद्धांजलि दी गई। ओएससीआई का उद्देश्य भारत में मैनुफैक्चरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। इसे गुजरात और हरियाणा में स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह केंद्र भारतीय सलाई चैन को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने के लिए कंपोनेंट निर्माताओं के स्टैंडर्ड को सुधारने में मदद करेगा। साथ ही, जापानी मैनुफैक्चरिंग फिलॉसफी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाएगा। यह पहल देश के मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र के भविष्य में अहम योगदान करेगी। मालूम हो कि ओसामु सुजुकी का 25 दिसंबर, 2024 को निधन हो गया था। स्वर्गीय ओसामु सुजुकी ने भारत में जापानी मैनुफैक्चरिंग पद्धतियों का परिचय कराया, जिसने न केवल मैनुफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया, बल्कि देश में समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज की दिशा में भी योगदान दिया। उनकी इन पद्धतियों के परिणामस्वरूप मारुति सुजुकी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और उनकी मैनुफैक्चरिंग फिलॉसफी को बढ़ावा देने के लिए ओएससीआई का गठन किया जा रहा है।

स्मार्टफोन्स रेजर 60 अल्ट्रा और एज 60 प्रो लांच



नई दिल्ली। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला के दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स रेजर 60 अल्ट्रा और एज 60 प्रो जल्द ही लॉन्च हो सकते हैं। यह स्मार्टफोन माउंटेन ट्रेल और स्कारब रंगों में दिखाई दिया है। वहीं मोटोरोला एज 60 प्रो को 12जीबी रैम 512जीबी स्टोरेज के लिए करीब 58,100 में लिस्ट किया गया है, जिसे डेजलिंग ब्लू और शेडो कलर में पेश किया जा सकता है। मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा का 16 जीबी रैम और 512जीबी स्टोरेज वैरिएंट लगभग 60 अल्ट्रा में स्नेपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट, 16जीबी रैम और 512जीबी स्टोरेज की उम्मीद है। इसका मेन फोल्डिंग डिस्प्ले 7 इंच का एलटीपीओ अमोलेड होगा, जो 165एचटो रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा, जबकि बाहर की ओर 4 इंच का कवर अमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50एमपी के दो रियर कैमरे और 50एमपी सेल्फी कैमरा हो सकता है। 4500एमएच बैटरी के साथ 68वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की भी जानकारी लीक हुई है। फोन का वजन 199 ग्राम और डायमेंशन 74.9गुना 171.5गुना 7.19 एमएम बताया गया है। इसमें रिंग होल्डर वाला प्रोटेक्टिव केस और दो साल की वारंटी भी मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, एज 60 प्रो में स्नेपड्रैगन 8जेन 2 प्रोसेसर और 12जीबी रैम मिल सकती है।

सरकार देशभर में ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध : राजू श्रीनिवास वर्मा

पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी केरल के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार देगी

नई दिल्ली

केंद्रीय भारी उद्योग, सार्वजनिक उद्यम और इस्पात राज्यमंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने शनिवार को कहा कि सरकार देशभर में अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वर्मा ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही, जहां राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) को उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे भारत में अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के बारे में बताया।

अपने संबोधन के दौरान वर्मा ने केरल के पलक्कड़ में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) को परिवर्तनकारी क्षमता की सराहना की और कहा कि यह परियोजना केरल और देश के व्यापक दक्षिणी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार देने के लिए तैयार है। इस



कार्यक्रम में भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में एनएलडीएसएल के योगदान को भी प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम पर केंद्रित एक तकनीकी सत्र भी शामिल था जिसमें आगामी पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी की रणनीतिक दृष्टि, योजना और प्रगति के बारे में गहन जानकारी दी गई। एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एक समर्पित सत्र में लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैनात किए जा रहे अभिनव डिजिटल समाधानों के बारे में विस्तार से बताया गया।

पुडुचेरी मध्य, पुडुचेरी पश्चिम और कन्नम्बरा में 1,710 एकड़ में फैला पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी केरल के औद्योगिक विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर है। पलक्कड़ शहर से 21 किमी, कोचीन से 120 किमी और

कोयंबटूर से 50 किमी दूर रणनीतिक रूप से स्थित यह परियोजना निर्बाध अंतरराष्ट्रीय संपर्क और महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक लाभ मुहैया कराती है। इसे सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के साथ शहर को उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को आकर्षित करने और क्षेत्रीय रोजगार तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

परियोजना की प्रमुख

उपलब्धियां-

- आवश्यक भूमि का 81 फीसदी हिस्सा पहले से ही कब्जे में है।
- सभी भूमि खंडों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी 01 जनवरी, 2025 को प्रदान कर दी गई है।
- परियोजना प्रबंधन और निर्माण परामर्शदाता को कार्य-निष्पादन पत्र जारी कर दिया गया है।
- ईपीसी निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर

है।

इस कार्यक्रम में भारत के लॉजिस्टिक्स तंत्र को बदलने में एनएलडीएसएल के योगदान को दर्शाया गया। सितंबर 2022 में अपनी स्थापना के बाद से यूएल ने 11 मंत्रालयों की 43 प्रणालियों को एकीकृत किया है जो 129 एपीआई और 1,800 से अधिक डेटा फील्ड के बिरफे जुड़ी हैं, 1,300 से अधिक पंजीकृत कंपनियों को सशक्त बनाया है और 100 करोड़ से अधिक एपीआई लेनदेन को सक्षम किया है। यह प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफॉर्म भारत में एकीकृत, कुशल और पारदर्शी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का उदाहरण है। उद्योग विकास कार्यक्रम में एनआईसीडीसी को मिलती मान्यता भारत के औद्योगिक परिवर्तन को गति देने तथा वैश्विक विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

शंघाई में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल एक्सपो



शंघाई में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल एक्सपो में पेश किये गये वाहन। इसमें 26 देशों के 1000 से ज्यादा वाहन निर्माता भाग ले रहे हैं।

हंटर 350, बुलेट 350 और सुपर मिटियोर 350 बाइक हो रही अपडेट

नई दिल्ली

पिछले साल रॉयल एनफील्ड द्वारा क्लासिक 350 के नए वर्जन को लॉन्च करने के बाद अब कंपनी हंटर 350, बुलेट 350 और सुपर मिटियोर 350 के अपडेट पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का अपडेटेड वर्जन 26 अप्रैल को आयोजित होने वाले हंटरहुड फेस्टिवल के दौरान लॉन्च किया जा सकता है।

अपकॉमिंग 2025 हंटर 350 में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। बाइक को नए कलर ऑप्शन और फ्रेश बॉडी ग्राफिक्स के साथ उतारा जा सकता है, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा आकर्षक हो जाएगा। इसके अलावा, हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखे गए मॉडल से



यह भी संकेत मिला है कि इसमें नया गोलाकार एलईडी हेडलैंप दिया जा सकता है, जो इसे मॉडर्न टच देगा।

हालांकि, बाइक के इंजन में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं बताई गई है। इसमें पहले की तरह 349सीसी का सिंगल-

सिलेंडर, एयर एंड ऑयल-कूल्ड, ओएचसी फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलेगा, जो 20.2 बीएचपी की पावर और 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन अपनी परफॉमेंस और रिलायबिलिटी के लिए काफी पसंद किया जाता है।

एप्पल किफायती मॉडल आईफोन 17ई पर कर रही है काम

नई दिल्ली

आईफोन बनाने वाली कंपनी ऐपल अपने अगले किफायती आईफोन मॉडल आईफोन 17ई पर काम कर रही है। यह डिवाइस पहले ही डायल प्रोडक्शन के करीब पहुंच चुका है, और आईफोन 17ई की लॉन्चिंग के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि, आईफोन 17 सीरीज का लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आईफोन 17ई को लेकर कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। एकरिपोर्ट के अनुसार, आईफोन 17ई की कीमत आईफोन 17 से कम होगी। इसकी डिजाइन आईफोन 16ई जैसी हो सकती है, जिसे 59,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। हालांकि, आईफोन 17ई की कीमत थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ऐपल इस मॉडल को किफायती रखने की कोशिश करेगा। इसमें ऐपल की अगली पीढ़ी की सी2 चिप हो सकती है, जो प्रोसेसिंग पावर में आईफोन 16ई से ज्यादा होगी। इसके अलावा, आईफोन 16ई में एआई फीचर्स का भी सपोर्ट



मार्च में 1.45 करोड़ लोगों ने भरी उड़ान, हवाई यात्रियों की संख्या 8.79 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली। देश में मार्च महीने में करीब 1 करोड़ 45 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी। हवाई यात्रियों की संख्या में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 8.79 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले साल (मार्च 2024) में कुल 133.68 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शनिवार को आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी। डीजीसीए ने अपनी मासिक घरेलू यात्री यातायात रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2025 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या 145.42 लाख थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह संख्या 133.68 लाख थी। इस तरह यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 8.79 फीसदी अधिक है। डीजीसीए के मुताबिक बीते महीने में इंडिगो ने कुल 93.1 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान की, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 64 फीसदी रही। एयर इंडिया समूह ने (पूर्ण सेवा प्रदाता एयर इंडिया और कम लागत वाली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस) के जरिए 38.8 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान की।

मिलने की संभावना है। टीएसएर फिक्स्ड फोकस डिजिटल ने बताया कि आईफोन 17ई की लॉन्चिंग मई 2026 में हो सकती है, हालांकि यह समयसीमा बदल भी सकती है। आईफोन 16ई की भारत में अच्छी मांग देखी गई थी, और आईफोन 17ई के लिए भी यही स्थिति बनी रहने की संभावना है, क्योंकि किफायती कीमत पर नया आईफोन मिलने का फैक्टरी यूजर्स के लिए आकर्षक है। हालांकि, ऐपल अपनी लॉन्चिंग के बारे में किसी प्रकार की घोषणा नहीं करता है, और जैसे पहले के मॉडल्स की तरह आईफोन 17ई का भी कोई टीज़र या संकेत नहीं होगा।

